



# राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शुक्रवार, 6 अप्रैल, 2007/16 चैत्र, 1929

हिमाचल प्रदेश सरकार

उच्चतर शिक्षा विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 16 जनवरी, 2007

संख्या ई० डी० एन०-ए०-क (1)-3/2005.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश प्राइवेट विश्व-विद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2006 (2006 का 12) की धारा 44 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम.—इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश प्राइवेट विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) नियम, 2006 है।

2. परिभाषाएं.—इन नियमों में, जब तक कि कोई बात विषय या संदर्भ में विरुद्ध न हो, —

(क) “अधिनियम” से हिमाचल प्रदेश प्राइवेट विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2006 (2006 का 12) अभिप्रेत है;

- (ख) "समिति" से अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (3) के अधीन गठित समिति अभिप्रेत है;
- (ग) "निदेशक" से निदेशक, उच्चतर शिक्षा, हिमाचल प्रदेश अभिप्रेत है ;
- (घ) "उच्चतर शिक्षा विभाग" से हिमाचल प्रदेश सरकार का उच्चतर शिक्षा विभाग अभिप्रेत है;
- (ङ) "जांच अधिकारी" से अधिनियम की धारा 43 की उप-धारा (3) के अधीन सरकार द्वारा नियुक्त जांच अधिकारी अभिप्रेत है; और
- (च) "विश्वविद्यालय" से अधिनियम के अधीन स्थापित विश्वविद्यालय अभिप्रेत है ।

(2) समस्त अन्य शब्दों और पदों के जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं परन्तु परिभाषित नहीं हैं, वही अर्थ होंगे, जो अधिनियम में उनके हैं ।

3. विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए आवेदन.—प्राइवेट विश्वविद्यालय की स्थापना करने का आशय रखने वाला प्रायोजक निकाय अपने प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्त्ता के माध्यम से सरकार को प्रस्तावों और परियोजना रिपोर्ट से युक्त (अन्तर्विष्ट) आवेदन प्रस्तुत करेगा ।

(2) आवेदन के साथ निदेशक, उच्चतर शिक्षा, हिमाचल प्रदेश के पक्ष में 10,00,000/- रूपए (दस लाख रूपए) की शिमला में संदेय, गैर-प्रतिदेय फीस, पाने वाले के खाते में (लेखे में) देय काँस बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से भेजी जाएगी ।

(3) आवेदन फीस से प्राप्त धन, निदेशक द्वारा समुचित प्राप्ति शीर्ष से निक्षिप्त (जमा) किया जाएगा और व्यय की पूर्ति करने के लिए वह यात्रा व्यय और कार्यालय व्यय के लिए आबंटन की मांग करेगा। वह इस प्रयोजन के लिए प्राप्ति और व्यय के पृथक लेखा-शीर्ष खोलेगा ।

4. प्रस्ताव की प्रक्रिया (प्रोसैसिंग).—(1) अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (3) के अधीन गठित समिति विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए प्रस्तुत प्रस्ताव की परीक्षा करेगी ।

(2) समिति ऐसे समय और स्थान पर बैठक करेगी जो सुविधाजनक हो ।

(3) समिति अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (4) के उपबन्धों के अनुसार प्रस्ताव की परीक्षा करेगी और प्रायोजक निकाय, ऐसी सूचना का प्रदाय करने और ऐसे निरीक्षणों जो समिति द्वारा वांछित हों, को सुकर बनाने के लिए कर्त्तव्य द्वारा आवद्ध होगा ।

5. समिति के अध्यक्ष और सदस्यों का यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता और अन्य भत्ते.—(1) समिति के प्रत्येक गैर-सरकारी सदस्य को 500/- रूपए प्रति बैठक मानदेय संदत्त किया जाएगा। जबकि समिति के गैर-सरकारी अध्यक्ष को 700/- रूपए प्रति बैठक मानदेय संदत्त किया जाएगा । इसके अतिरिक्त वे ऐसे यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते के हकदार होंगे जैसे सरकार के ग्रेड-1 अधिकारियों को अनुज्ञेय हैं ।

(2) गैर-सरकारी अध्यक्ष/सदस्य यात्रा करने हेतु अपनी कार/टैक्सी का प्रयोग कर सकेंगे तथापि, प्रति-पूर्ति सरकार द्वारा समय-समय पर यथा अनुमोदित दरों के अनुसार निर्बंधित की जाएगी ।

(3) सरकारी (शासकीय) सदस्य, पदीय कर्तव्य पर अपनी हकदारी के अनुसार, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते के हकदार होंगे और अपने-अपने कार्यालयों से उसका आहरण करेंगे।

(4) उप-नियम (1) और (2) के अधीन उपगत किया जाने वाला समस्त व्यय, व्यय के लेखा-शीर्ष से प्रभारित किया जाएगा।

6. विन्यास निधि का समग्रहरण.—(1) यदि विश्वविद्यालय या प्रायोजक निकाय अधिनियम या तदधीन बनाए गए निम्नों, परिनियनों, अध्यादेशों अथवा विनियमों के किसी भी उपबन्ध का उपबन्धन करता है तो सम्पूर्ण विन्यास निधि या उसका अंश सरकार द्वारा समग्रहृत किया जा सकेगा, परन्तु ऐसे समग्रहरण से पूर्व सरकार द्वारा यथास्थिति प्रायोजक निकाय या विश्वविद्यालय पर कारण बताओ नोटिस तामील किया जाएगा।

(2) सरकार अन्य बातों के साथ, प्रायोजक निकाय/विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तुत उत्तर पर सम्यक रूप से विचार करेगी।

(3) यदि प्रायोजक निकाय या विश्वविद्यालय द्वारा उप-नियम (1) के अधीन जारी कारण बताओ नोटिस का उत्तर, नोटिस के जारी होने के 45 दिन के भीतर प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो सरकार ऐसे उत्तर की प्रतीक्षा किए बगैर ही मामले का निश्चय कर सकेगी।

(4) विन्यास निधि की समग्रहृत राशि सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाने वाली रीति में उपयोग में लायी जाएगी।

7. निरीक्षण.—(1) सरकार अधिनियम की धारा 41 के अधीन दृष्ट (परिकल्पित) निरीक्षण का कार्य अध्यापन, परीक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में विशेष जान रखने वाले किसी व्यक्ति (व्यक्तियों) को सौंप सकेगी। इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति, जैसा वह समुचित समझे, ऐसी बैठकें, जांच और निरीक्षण कर सकेगा/सकेंगे।

(2) उपरोक्त उप-नियम (1) के अधीन नियुक्त व्यक्ति, यदि गैर-सरकारी है/हैं, तो यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते, जैसा कि राज्य सरकार के ग्रेड-1 अधिकारियों को अनुज्ञेय है, के अतिरिक्त 500/- रुपये प्रतिदिन प्रति व्यक्ति मानदेय के हकदार होंगे। वे यात्रा करने हेतु अपनी कार/टैक्सी का उपयोग कर सकेंगे। तथापि प्रतिपूर्ति, सरकार द्वारा समय-समय पर अनुमोदित दरों के अनुसार निर्बंधित की जाएगी।

(3) उप-नियम (2) के अधीन उपगत किया जाने वाला व्यय, व्यय के लेखा-शीर्ष से प्रभारित किया जाएगा।

8. विश्वविद्यालय का समापन और प्रशासक की नियुक्ति—(1) अधिनियम की धारा 43 की उप-धारा (3) के उपबन्ध के अधीन नियुक्त जांच अधिकारी(यों) को, यदि गैर-सरकारी है तो राज्य सरकार के ग्रेड-1 अधिकारियों को यथा अनुज्ञेय यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता, संदत्त किया जाएगा।

(2) जांच अधिकारी सामान्यतः 45 दिन के भीतर जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा(गें), तथापि, सरकार असाधारण परिस्थितियों में जिसके कारण लिखत में अभिलिखित किए जाएंगे, इसके लिए विस्तार प्रदान कर सकेगी।

(3) अधिनियम की धारा 43 की उप-धारा (6) के अधीन नियुक्त प्रशासक वेतन, भत्ते और अन्य परि-लब्धियों, जैसे कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की जाएं, का हकदार होगा तथा इस निमित्त व्यय का वहन विश्वविद्यालय द्वारा किया जाएगा।

9. शिथिल करने की शक्ति.—जहां सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, तो वह इन नियमों के किसी भी उपबन्ध(उपबन्धों) को शिथिल कर सकेगी।

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित/-  
प्रधान सचिव।

[Authoritative English text of this Department Notification No. EDN-A-Ka (1)-3/2005, dated 16-1-2007 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

## HIGHER EDUCATION DEPARTMENT

### NOTIFICATION

Shimla-2, the 16th January, 2007

**No. EDN-A-Ka(1)-3/2005.**—In exercise of the power conferred by section 44 of the Himachal Pradesh Private Universities (Establishment and Regulation) Act, 2006 (Act No. 12 of 2006), the Governor, Himachal Pradesh is pleased to make the following rules for carrying out the purpose of the said Act, namely :—

1. *Short title.*—These rules may be called the Himachal Pradesh Private Universities (Establishment and Regulation) Rules 2006.

2. *Definitions.*—In these rules, unless there is anything repugnant in the subject or context,—

- (a) “Act” means the Himachal Pradesh Private Universities (Establishment and Regulation) Act, 2006 (No. 12 of 2006) ;
- (b) “Committee” means the Committee constituted under sub-section (3) of section 4 of the Act;
- (c) “Director” means the Director of Higher Education, Himachal Pradesh;
- (d) “Higher Education Department” means the Higher Education Department of Himachal Pradesh Government;
- (e) “Inquiry officer” means an inquiry officer appointed by the Government under sub-section (3) of section 43 of the Act; and
- (f) “University” means the university established under the Act.

(2) All other words and expression used in these rules but not defined therein shall have the same meaning respectively as assigned to them in the Act.

3. *Application for establishment of university.*—(1) A sponsoring body intending to establish a private university shall submit an application containing proposals and the project report through its authorized signatory to the Government.

(2) A non-refundable fee of Rs. 10,00,000/- (Rupees Ten lacs) shall be sent alongwith application through crossed account payee bank draft in favour of the Director, Higher Education, Himachal Pradesh payable at Shimla.

(3) The money received on account of application fee shall be deposited by the Director in an appropriate receipt head and he shall seek allocation on Travel Expenses and Office Expenses to meet expenses. He shall open separate heads of accounts of receipt expenditure for this purpose.

4. *Processing of the proposal.*—(1) The committee constituted under sub-section (3) of section 4 of the Act shall examine the proposal submitted for the establishment of a university.

(2) The committee shall meet at such time and place as may be convenient.

(3) The committee shall examine the proposal as per the provisions of sub-section 4 of section 4 of the Act and the sponsoring body shall be duty bound to supply such information and facilitate such inspections as may be required by the committee.

5. *Travelling allowance/daily allowance and other allowances of the Chairman and members of the Committee.*—(1) Every non-official member of the committee shall be paid honorarium of Rs. 500/- per sitting. The non-official Chairman of the committee shall however, be paid an honorarium of Rs. 700/- per sitting. Besides, they shall be entitled to travelling allowance/daily allowance as admissible to Grade-I Officers of the Government.

(2) The non-official Chairman/members may use their own car/taxi to perform journey. However, the reimbursement shall be restricted to the rates as approved by the Government from time to time.

(3) The official members shall be entitled to travelling allowance/daily allowance as per their entitlement on official duty and shall draw the same from their respective offices.

(4) The entire expenditure to be incurred under sub-rules (1) and (2) shall be charged to the head of account of expenditure.

6. *Forfeiture of Endowment Fund.*—(1) In case the university or the sponsoring body contravenes any of the provisions of the Act, rules, statutes, ordinances or regulations made thereunder, a part or whole of the Endowment Fund may be forfeited by the Government but before such forfeiture, a show cause notice shall be served by the Government on the sponsoring body or the university, as the case may be.

(2) The Government shall among other things, duly consider the reply submitted by the sponsoring body/university.

(3) In case the reply to show cause notice issued under sub-rule (1), is not submitted by the sponsoring body or the university within 45 days of the issue of notice, the Government may decide the case without waiting for such reply.

(4) The forfeited amount of Endowment fund shall be used in the manner to be specified by the Government.

7. *Inspections.*—(1) The Government may entrust the work of inspection envisaged under section 41 of the Act to any person(s) having special knowledge in the field of standards of

teaching, examination and research. The person(s) so appointed may hold such meetings, enquiries and inspections as they deem appropriate.

(2) The person(s) appointed under rule (1) supra, if non-official, shall be entitled to honorarium of Rs. 500/- per day per person besides travelling allowance/daily allowance as admissible to Grade-I officers of the State Government. They may use their own Car/Taxi to perform journey. However, the reimbursement shall be restricted to the rates approved by the Government from time to time.

(3) The expenditure to be incurred under sub-rule (2) shall be charged to the head of account of expenditure.

8. *Liquidation of the university and appointment of administrator.*—(1) The inquiry officer(s) appointed under the provision of sub-section (3) of section 43 of the Act if non-official shall be paid travelling allowance/daily allowance as admissible to Grade-I Officers of the State Government.

(2) The inquiry officer(s) shall ordinarily submit inquiry report within 45 days. However, the Government may in exceptional circumstances grant extension for reasons to be recorded in writing.

(3) The administrator appointed under sub-section (6) of section 43 of the Act shall be entitled to salary, allowance and other perks as may be notified by the State Government and the expenditure on this account shall be borne by the university.

9. *Power to relax.*—Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may relax any of the provision(s) of the these rules.

By order,

Sd/-  
Principal Secretary.